

पेसा अधिनियम

प्रलिस के लयः

पेसा अधनलडड के डुरावधान, अनुकृडेद 244(1), डारत डें जनजातीय नीतड

डेनुस के लयः

पेसा अधनलडड से संबंघतड डुदडे, पेसा अधनलडड को लागू करने के लाभ ।

कुरकड डें कुरडें?

गुजुरात डें वडडनलन कुरनावी दल **डंकायत डुडबंध (अनुसूकतड कषुतुरडें तक वसुतार) अधनलडड (पेसा), 1996** को सखुती से लागू करने का वडद करके आदवलसडडड को लुडडने की कोशश डर रहे हैं ।

- गुजुरात डें जनवरी 2017 डें राजुड पेसा नडडडड को अधसुुकतड कडडड डया आर उनुहें राजुड के आठ कुलडड के 50 आदवलसी तालुकु के 2,584 ग्रडड डंकायतु के तहत 4,503 ग्रडड सडडडड डें लागू कडडड डया ।
- हालुडक अधनलडड को अभी डी अकषुरशः लागू नुही कडडड डया है ।
- कुरह राजुडु (हडडडल डुरदेश, आंधुर डुरदेश, तेलंगडनड, राजसुथडन, गुजुरात, डडरडषुतुर) ने पेसा कडनून डनडड है आर डदडडे नडडड लागू हुते हैं तो कुरतुतडसगदु इनुहें लागू करने वडलड सडतवुडु राजुड डन डडडडड ।

पेसा अधनलडडः

- डुरकडडः
 - पेसा अधनलडड 1996 डें "डंकायतु से संबंघतड सुवडडडन के डडडड IX के डुरडवडडनु के अनुसूकतड कषुतुरडें डें वसुतारतड करने के लडडड" अधनलडडडड कडडड डया थड ।
 - सुवडडडन के अनुकृडेद **243-243ZT के डडडड IX** डें नगर डडलकडडडु आर सहकडरड सडतडडडडु से संबंघतड डुरडवडडन है ।
- डुरडवडडनः
 - इस अधनलडडड के तहत **अनुसूकतड कषुतुर डे हैं जनडुहें अनुकृडेद 244 (1) डें सुदरुडडतड कडडड डया है**, डसुके अनुसडर डडुंकवी अनुसूकड के डुरडवडडन असडड, डेघडलडड, तुरडडडर आर डडुडुरड के अलडवड अनुड राजुडु डें अनुसूकतड कषुतुरडें के अनुसूकतड जनजातडडडु डर लागू हुुगे ।
 - डडुंकवी अनुसूकड इन कषुतुरडें के लडडड वशडष डुरडवडडनु की शुरुखुलड डुरदडन करतुतु है ।
 - दस राजुडु- आंधुर डुरदेश, कुरतुतुसगदु, गुजुरात, हडडडल डुरदेश, डडरखंड, डधुड डुरदेश, डडरडषुतुर, ओडशडड, राजसुथडन आर तेलंगडनड ने डडुंकवी अनुसूकड के कषुतुरडें को अधसुुकतड कडडड है जो इन राजुडु डें से डुरतुतुडड डें कडु डडडु (आंशकड डड डुरी तरह से) को कवर करते हैं ।
- उदुदेशुडः
 - अनुसूकतड कषुतुरडें डें रहने वडले लुगेु के लडडड **गुरडड सडडडडु** के डडधुडड से सुवशडसन सुनशुकतड करनड ।
 - डह कडनूनी रूड से आदवलसी सडुदडडु, अनुसूकतड कषुतुरडें के नवलसडडडु के अधकडर को सुवशडसन की अडडनी डुरणलडडडु के डडधुडड से सुवडु को शडसतड करने के अधकडर को डडनुडतड देतड है । डह डुरडकृतकड सुंसडधनुु डर उनके डडरुडरकड अधकडरुु को सुवीकर करतड है ।
 - गुरडड सडडडडु को वकडस डुडडनडु को डडुडुरी देने आर सडडु सडडडडकड कषुतुरडें को नडडुतुरतड करने डें डहतुतुवडुरण डुडडकड नडडडने कड अधकडर देतड है ।

पेसा अधनलडड डें गुरडड सडड कड डहतुतुवः

- **लुकतडतुरकड वकडुदुरीकरणः** पेसा गुरडड सडडडडु को वकडस डुडडनडु की डडुडुरी देने आर सडडु सडडडडकड कषुतुरडें को नडडुतुरतड करने डें डहतुतुवडुरण डुडडकड नडडडने कड अधकडर देतड है । इस डुरडंधन डें नडडनलखडतड शडडलडड हैः
 - डल, डंगल, डडडडन डर सुंसडधन ।
 - **लघु वनोतुडडड** ।

- मानव संसाधन: प्रक्रियाएँ और कार्मिक जो नीतियों को लागू करते हैं।
 - स्थानीय बाजारों का प्रबंधन।
 - भूमि अलगाव को रोकना।
 - नशीले पदार्थों को नयित्तरति करना।
- **पहचान का संरक्षण:** ग्राम सभाओं की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नयित्तरण एवं एक गाँव के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर नयित्तरण शामिल है।
 - **संघर्षों का समाधान:** इस प्रकार पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों तथा परविश के सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
 - **पब्लिक वॉचडॉग:** ग्राम सभा को अपने गाँव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परविहन, बिक्री और खपत की निगरानी तथा निषिध करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

पेसा से संबंधित मुद्दे:

- **आंशिक कार्यान्वयन:** राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिये राज्य कानूनों को अधिनियमित करना चाहिये।
 - इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ है।
 - आंशिक कार्यान्वयन ने आदवासी क्षेत्रों, जैसे- झारखंड में स्वशासन को विकृत कर दिया है।
- **प्रशासनिक बाधाएँ:** कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परिवर्तन के प्रतिरोध आदि के कारण सफल नहीं हुआ।
- **वास्तविकता के स्थान पर कागज़ी अनुसरण:** राज्य भर में किये गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया है कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा और नयित्तरण लेने के लिये कोई बैठक नहीं हुई थी।

भारत की जनजातीय नीति:

- भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारतीय संविधान का **भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र** में निति **अनुच्छेद 244** (अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनयित्तरण के अधिकार (Right to Self-determination) की गारंटी दी गई है।
 - संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नयित्तरण तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किये गए हैं।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में वसितार) अधिनियम 1996** या **पेसा अधिनियम**।
- जनजातीय पंचशील नीति।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006** वन में रहने वाले समुदायों के भूमि एवं अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

आगे की राह

- यदि पेसा अधिनियम को अक्षरशः लागू किया जाता है, तो यह आदवासी क्षेत्र में मरती हुई स्वशासन प्रणाली को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करने और इसे अधिकि-समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने का अवसर भी देगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस